माननीय न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल के समक्ष

ठकरद्वारा कलां, तालाब नौरंग राय में स्थापित मूर्ति श्री राम चंदर जी महाराज

बनाम

हरियाणा राज्य और एक अन्य - उत्तरदाता।

सिविल संशोधन सं. *1986* ***का*** *2806*

17 ***फरवरी,*** *1987।*

*भूमि अधिग्रहण अधिनियम (*1894 का) - *धारा* 9. 18 *और* 30 - *नागरिक प्रक्रिया संहिता* (1908 का V) - *आदेश 1, नियम 10 - मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार - वह व्यक्ति जो संदर्भ में पक्षकार नहीं है कलेक्टर के निर्णय के विरुद्ध अपील में पहली बार अधिकार लागू करने का अनुरोध कर रहा है- अपीलीय स्तर पर ऐसे आवेदक को उचित मानना-* क्या *अनुमति दी जा सकती है।*

यह अभिनिर्णित किया गया है, कि एक व्यक्ति जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 9 के तहत कलेक्टर के समक्ष कोई दावा नहीं करता है, न ही अधिनियम की धारा 30 के तहत संदर्भ के लिए कोई आवेदन करता है, जो मुआवजे को प्राप्त करने के अपने अधिकार पर जोर देता है, उस व्यक्ति के विपरीत जिसने मुआवजे की वृद्धि के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ प्राप्त किया था, उन्हें नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के नियम 10 के आदेश 1 के तहत खुद को एक पक्ष के रूप में शामिल करने और उस संदर्भ में मुआवजा प्राप्त करने के अपने अधिकार को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर अधिनियम की धारा 18 के तहत कलेक्टर द्वारा किए गए संदर्भ पर जुर्माना लगाया जाता है और यह संहिता के आदेश 1, नियम 10 के प्रावधानों को लागू करके इसके दायरे को नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि अपीलीय स्तर पर एक पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए छुट्टी की मांग करने वाले आवेदन को अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(पैरा 4)

अंबाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री जे के सूद के दिनांक 1 सितंबर, 1986 के आदेश की धारा 115 सी.पी.सी., अनुच्छेद 227 और पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 44 के तहत संशोधन के लिए याचिका, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के नियम 10 के आदेश 1 के तहत आवेदन को एक पक्ष के रूप में शामिल करने के लिए खारिज कर दिया गया था।

याचिकाकर्ता की ओर से- एसके गोयल, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए - एम. एस. सुल्ल।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एस.पी. गोयल,

1. ठाकुरद्वारा कलां तालाब नौरंग राय, अंबाला शहर से संबंधित कुछ भूमि का अधिग्रहण हरियाणा राज्य द्वारा किया गया था। कलेक्टर द्वारा दिए गए मुआवजे से असंतुष्ट महंत राम नारायण दास, प्रतिवादी नंबर 2 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 18 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत संदर्भ मिला। जब मामला अंबाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में साक्ष्य के स्तर पर था, तो ट्रस्ट ठाकुरद्वारा कलां ने अपने उपाध्यक्ष हित अभिलाषी के माध्यम से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के तहत एक पक्ष के रूप में शामिल होने के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसमें प्रार्थना की गई कि यह ट्रस्ट था जो केवल ठाकुरद्वारा के मामलों का प्रबंधन करने का हकदार था और मुआवजे का भी हकदार था। प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा आवेदन का विरोध किया गया था और अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने ***निरंजन सिंह बनाम अमर सिंह, 1985 आरआरआर 655: एआईआर 1984 पंजाब और हरियाणा 250*** में इस अदालत के एक फैसले पर भरोसा करते हुए इसे खारिज कर दिया था। इसलिए ट्रस्ट द्वारा यह संशोधन याचिका दायर की गई है।

2. शुरुआत में, याचिकाकर्ता-ट्रस्ट के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि चूंकि ***भाग सिंह और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, जिला न्यायालय जालंधर, 1984 पीएलआर 568*** मामले में इस न्यायालय के दो एकल-पीठ के फैसलों के बीच स्पष्ट रूप से विरोधाभास है और निरंजन सिंह के मामले (सुप्रा) को एक बड़ी पीठ को भेजा जाए। हालांकि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में कुछ मतभेद प्रतीत होते हैं, लेकिन उपरोक्त दो निर्णयों को ध्यान से पढ़ने से पता चलेगा कि वे प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों पर प्रस्तुत किए गए थे। निरंजन सिंह के मामले (सुप्रा) में अमर सिंह और ग्राम पंचायत के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद को पूर्व के इशारे पर अधिनियम की धारा 30 के तहत संदर्भित किया गया था। निरंजन सिंह और कुछ अन्य व्यक्तियों ने आवेदक या प्रतिवादी के रूप में शामिल होने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के तहत अदालत में एक आवेदन दिया, जिसे खारिज कर दिया गया। कांग, जे ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा: -

"धारा 30 के तहत कलेक्टर द्वारा किए गए संदर्भ पर अदालत के समक्ष कार्यवाही एक विशेष प्रकृति की है। न्यायालय अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के बंटवारे के संबंध में विवाद का केवल एक संदर्भ पर संज्ञान ले सकता है और जांच कुछ पक्षों के बीच विवाद तक ही सीमित है। न्यायालय दूसरों को पक्षकार बनाकर अपना दायरा नहीं बढ़ा सकता। जिन व्यक्तियों ने कलेक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे और विवाद में भूमि के लिए मुआवजे के लिए कोई दावा नहीं किया था, और कलेक्टर के फैसले में मुआवजे के बंटवारे के बारे में कोई शिकायत नहीं उठाई है, वे संदर्भ पर निर्णय लेने वाले न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे में शामिल होने के लिए आगे नहीं आ सकते हैं।

3. इसमें कोई संदेह नहीं है कि***माउंट सकलबासो कुएर बनाम बृजेन्द्र सिंह और अन्य, एआईआर 1967 पटना 243*** में इस प्रश्न पर की गई टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया गया था कि क्या कोई व्यक्ति, जिसने अधिनियम की धारा 30 के तहत किसी भी संदर्भ का दावा नहीं किया था, को न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाया जा सकता है या नहीं, लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने कभी नहीं कहा कि आदेश 1 के प्रावधान, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता, लागू नहीं थी या किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति को उक्त शक्तियों को लागू करके संदर्भ में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता था। भाग सिंह के मामले (सुप्रा) में, सह-हिस्सेदारों में से एक द्वारा मुआवजे को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ दिया गया था। एक अन्य सह-हिस्सेदार ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसे आई.एस. तिवाना, जे. द्वारा सक्षम माना गया था, और प्रार्थना से निपटने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को उलट दिया गया था। निरंजन सिंह के मामले (सुप्रा) में जिस तर्क के आधार पर अजनबी द्वारा आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था। जाहिर है कि बाग सिंह के मामले (सुप्रा) के तथ्यों पर कोई प्रयोज्यता नहीं थी, क्योंकि बाद के मामले में संदर्भ के दायरे या प्रकृति को संदर्भ में एक पक्ष के रूप में किसी अन्य सह-शेयरधारक को शामिल करके किसी भी तरह से बढ़ाया या बदला नहीं जा रहा था। इस प्रकार, कानून के किसी भी सवाल पर दो फैसलों में कोई विरोधाभास नहीं होने के कारण, एक बड़ी पीठ को संदर्भित करने के अनुरोध को अस्वीकार करना होगा।

4. वर्तमान मामले में, मेरे लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि मैं कोई सुविचारित राय व्यक्त करूं कि निरंजन सिंह के मामले (सुप्रा) का फैसला सही तरीके से किया गया था या नहीं। यहां, संदर्भ में विभाजन का कोई प्रश्न शामिल नहीं है और न्यायालय को संदर्भित एकमात्र विवाद ठाकुरद्वारा से संबंधित भूमि के बाजार मूल्य के प्रश्न पर था। यदि दो व्यक्तियों के बीच विभाजन के प्रश्न को अधिनियम की धारा 30 के तहत संदर्भित किया गया था, तो तीसरे पक्ष के लिए यह संभव हो सकता था कि वह खुद को पक्षकार बनाने के लिए आदेश 1, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दायर कर सकता था। लेकिन, ऐसे आवेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा जब संदर्भ का दायरा केवल उचित बाजार मूल्य तक ही सीमित हो।

न्यायालय का अधिकार क्षेत्र धारा 18 के तहत कलेक्टर द्वारा किए गए संदर्भ तक ही सीमित है और यह प्रावधान या आदेश 1, नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता को लागू करके इसके दायरे को नहीं बढ़ा सकता है। यदि किसी संदर्भ में विभाजन का प्रश्न शामिल था, तो एक अजनबी, जिसने कलेक्टर के समक्ष कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था, किसी दिए गए मामले में, विभाजन के विवाद को अंतिम रूप से निपटाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1, नियम 10 के तहत शक्तियों का उपयोग करके पक्षकार बनाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले की तरह किसी तीसरे पक्ष को पक्षकार बनाने के लिए ऐसा कोई विचार उपलब्ध नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से कलेक्टर के दायरे में वृद्धि होगी। संदर्भ और, वास्तव में, एक नया विवाद पेश करेगा जो पहले से ही संदर्भ द्वारा कवर नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को यह भेद बताए जाने के बावजूद, वह एक भी निर्णय पेश नहीं कर सका, जिसमें किसी तीसरे व्यक्ति की याचिका को स्वीकार कर लिया गया था, जबकि संदर्भ में मुआवजे के विभाजन का कोई सवाल नहीं था। सभी तीन निर्णयों में अर्थात् माउंट सकलबासो कुएर का मामला (सुप्रा), ***भादर मुंडा और अन्य बनाम धुचुआ उरांव, एआईआर 1970 पटना 209***, और ***कलारिक्कल लक्ष्मीकुट्टी अम्मा बनाम कंकाथ वेटोलिल कन्हिरापल्ली, एआईआर 1973 केरल 79***, जिस पर उन्होंने भरोसा किया, प्रतिद्वंद्वी दावेदारों और मुआवजे प्राप्त करने के अधिकार का दावा करने वाले तीसरे व्यक्ति के बीच विभाजन से संबंधित संदर्भों को अंतिम रूप से एक पक्ष के रूप में शामिल करने का आदेश दिया गया था। नतीजतन, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, याचिकाकर्ता, जिसने अधिनियम की धारा 30 के तहत कलेक्टर के समक्ष मुआवजा प्राप्त करने के अपने अधिकार पर जोर देने के लिए कभी कोई दावा नहीं किया, उन व्यक्तियों के विपरीत जिन्होंने मुआवजे को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ प्राप्त किया था , उन्हें आदेश 1 के तहत खुद को एक पक्ष के रूप में शामिल करने का कोई अधिकार नहीं होगा। नियम 10, सिविल प्रक्रिया संहिता, और मुआवजा प्राप्त करने का उसका अधिकार उस संदर्भ में तय किया गया। इसलिए, यह याचिका विफल होनी चाहिए और इसे खारिज किया जाता है, लेकिन लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अक्षय अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा